sector banks as also the actual achievement of banks in West Bengal in regard to flow of credit to the key areas during the year 1987 along with the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): The information is being collected and will be laid on the Table of the House to the extent possible.

मध्य प्रदेश में बेरो[illegible]तियों को सहायता

3462. **श्री अजीत जोगी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में ऐसे नगरीय बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्होंने गत दो वर्षों के दौरान एस०ई० पी.यू.पी. योजना के अधीन उन्हें प्रदान की गई सहायता का उचित उपयोग किया है और क्या वे वस्तुतः अपने रोजगार में कार्यरत है ;

(ख) क्या योजना के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिये कोई प्रक्रिया अपनाई जायेगी ताकि इस योजना के अधीन लाभ सही व्यक्तियों को मिल सके और वे उन लाभों का उचित उपयोग कर सकें; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में वार्षिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री [illegible]लेरियो) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि गत दो वर्षों में मध्य प्रदेश में शहरी गरीबों के लिये स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत मंजूर किये गये ऋण और संवितरित की गई राशि का वितरण इस प्रकार है.--

(लाख रुपयों में)

वर्ष	मंजूर किये गये ऋण		संवितरित किये गये ऋण	
	संख्या	राशि	संख्या	
1986-87 . . .	23364	869.84	19630	690.56
1987-88 . . .	22915	999.91	16977	705.96

शहरी [illegible] के लिये स्वरोजगार योजना के हितार्थिकारियों का चयन स्थानीय बैंकरों की गठित समिति द्वारा किया जाता है । यह समिति आवेदनों को संबंधित बैंक शाखाओं के पास भेजने से पहले उनकी जांच करती है । बैंक शाखायें इन आवेदनों का मूल्यांकन करती है और मंजूरी से पहले सर्वेक्षण करती हैं और ऋण-कर्ता की पात्रता और परियोजना की अर्थ-क्षमता के संबंध में संतुष्ट होने के बाद ही स्वीकृति प्रदान करती हैं । बैंक शाखायें समुचित अनुवर्ती कार्रवाई और निगरानी द्वारा ऋण के अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करती हैं ।

स्वतंत्रता सैनानियों की [illegible] में वृद्धि

3463. **श्री [illegible] :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वतंत्रता सेनानियों को दी जा रही पेंशन की राशि में कोई वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय ले लिये जाने की संभावना है और उसमें किस हद तक वृद्धि किये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) स्वतंत्रता सेनानियों को दी जा रही पेंशन की राशि में अभी तक कोई वृद्धि नहीं की गई है ।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के कार्यान्वयन से प्रभावित आदिवासियों को सुविधाओं का दिया जाना

3464. **श्री अजीत जोगी** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चूंकि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के लागू होने के बाद, आदिवासियों को उनकी आजीविका के लिये कोई अतिरिक्त भूमि आवंटित नहीं की जा सकी है और वनोपज तथा वन विभाग द्वारा उन्हें दी जा रही मजदूरी भी उनके लिये कम होती जा रही है इसलिये क्या सरकार वनों में आदिवासियों की आजीविका के स्रोत जुटाने के लिये कोई उपाय करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इन आदिवासियों को विस्तृत वन-क्षेत्र में हल्दी, पाईनएपल, टेपीयोका, अरबी, खरीफ, आलू आदि जैसी पेड़ों की छाया में पैदा हो सकने वाली फसलों और नीबू, संतरा आदि जैसे फलदार पेड़ों को लगाने की अनुमति दी जायेगी ताकि वे अपनी आजीविका अर्जित कर सकें ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जैड० आर० अंसारी): (क) और (ख) गैर-वन प्रयोजनों के लिये वन भूमि को उपयोग में लाने के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होती है। वन भूमि पर आदिवासियों के प्रथागत अधिकारों को वन कार्य योजनाओं के तहत सुरक्षा प्रदान की जाती है। वानिकी क्षेत्र में तीन स्कीमें आरम्भ की गई हैं जिनमें वर्ष 1988-89 के दौरान केवल आदिवासी क्षेत्रों में खर्च किये जाने के लिये 885.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये है । (**नीचे देखिये**)

(ग) सरकारी वन भूमि में कृषि और बागवानी में संबंधित फसलों की खेती करने की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है ।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	स्कीम	कुल परिव्यय	आदिवासी क्षेत्र हेतु निर्धारित निधियों की मात्रा	प्रतिशत
1.	वन चरागाह फार्मों की स्थापना	400.00	95.00	24
2.	ग्रामीण जलाऊ लकड़ी को पौधरोपण सहित सामाजिक वानिकी	1700.00	490.00	28
3.	हिमालय क्षेत्र में समन्वित मृदा और जल संरक्षण स्कीम	1200.00	300.00	25

वृक्षारोपण के अन्तर्गत लाई गई बंजर भूमि

3465. **श्री अजीत जोगी** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान वर्षा ऋतु के दौरान बंजर भूमि विकास बोर्ड द्वारा कितनी बंजर भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है;

(ख) क्या यह लक्ष्य के अनुरूप था; और

(ग) मध्य प्रदेश में बंजर भूमि में वृक्षारोपण के काम में तेजी लाने के लिये बोर्ड द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जैड० आर० अन्सारी) : (क) और (ख) वनी-